

भाजपा राहुल गांधी को घेरने की फिराक में है

पर, पार्टी में मतभेद हैं कि राहुल को पुनः संसद से “डिस्क्वालिफाई” करा दिया जाता है तो वे “हीरो” के रूप में उभर सकते हैं तथा जनता में उनके प्रति सहानुभूति उभरेगी

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। भाजपा ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कमर कस ली है, और उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उसे लेकर भाजपा कार्रवाई करना चाहती है।

यह अवसर आज तब आया, जब बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम एप्टीन फाइल्स में शामिल होने के संबंध में लिया।

इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी पर दबाव था, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में एक मामला चल रहा था, और चूंकि अडानी मोदी के वित्तीय सहयोगी और आर्किटेक्ट हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव था और उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मामले में

- पर, दूसरी सोच यह है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है तथा अगर भाजपा से नज़दीकी रखने वाले चुनाव आयुक्त हों तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव छः महीने नहीं होने दे।
- पर, बहरहाल अभी तो इस बात पर भाजपा में आम सहमति बनी है कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन में “प्रिविलेज” प्रस्ताव तो लाया ही जाए, जिस तरह बजट पर बोलते हुए उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी व बिज़नैसमैन अनिल अंबानी पर लांछन लगाया कि उनके नाम “एप्टीन फाइल्स” में आये हैं।
- भाजपा, इस बात से भी काफी उत्तेजित है कि जिस तरह राहुल गांधी ने प्र.मंत्री पर कई आरोप लगाए, अमेरिका के सामने आत्म समर्पण किया। पर, दुविधा यह है कि भाजपा निश्चित नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी से किस तरह डील किया जाए।

ट्रम्प के सामने समर्पण कर दिया। सूत्रों का कहना है कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार और भाजपा में इस पर मतभेद है कि क्या राहुल गांधी को सदन की सदस्यता

के अयोग्य ठहराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

एक गुट का मानना है कि यह कदम अक्लमंदी नहीं होगा, क्योंकि इससे राहुल गांधी एक “हीरो” बन जाएंगे तथा और अधिक लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे।

दूसरा गुट, जो सख्त रुख अपनाए हुए है, उसका कहना है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए। यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सरकार का आज्ञाकारी चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव 6 महीने से पहले नहीं कराए जाएं।

लेकिन वे राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहते हैं। राहुल गांधी के मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ तीखे शब्दों ने सरकार को आहत किया है, लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘तीन साल से एक जगह तैनात अफसरों का तबादला होगा’

कोलकाता, 11 फरवरी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया

- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किया बड़ा फैसला।

है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। निर्देश के अनुसार, यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) , उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) , पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता’

नई दिल्ली, 11 फरवरी। केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन से रिहा नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ को बताया कि अदालत के अनुरोध पर स्वास्थ्य आधार पर डिटेंशन को समीक्षा के लिए गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। मेहता ने कहा कि जेल मेनुअल के अनुसार, वांगचुक की 28 बार चिकित्सकीय जांच की गई है और वे स्वस्थ, ठीक-

- केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया।

ठाक और सामान्य हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ पाचन संबंधी समस्या हुई थी, जिसका इलाज चल रहा है और कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पिछली सुनवाई में जस्टिस वराले ने मौखिक रूप से वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई थी और डिटेंशन पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था, जिस पर न्यायमूर्ति कुमार ने भी सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केंद्र सरकार वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को पूरी तरह नकार रही हो।

बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी का रुख भारत के प्रति नरम हुआ

जमात के नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के लिए बेहद जरूरी हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 फरवरी। बांग्लादेश में गुस्से को होने वाले अहम चुनाव से एक दिन पहले, जिसमें नई सरकार चुनी जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, जमात का एक प्रमुख उम्मीदवार चर्चा में है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासेम अरमान एक हाई-प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं।

अगस्त 2024 से बांग्लादेश में मुहम्मद युनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, क्योंकि जुलाई 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को हटा दिया गया था।

तब से ध्यान इस बात पर है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पर कौन शासन करेगा। इस दौड़ में दो मुख्य दावेदार हैं,

- जमात के एक कद्दावर नेता, मीर अहमद बिन कासेम अरमान, जो ढाका-14 से चुनाव लड़ रहे हैं, का मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ताकतवर नेता संजीदा इस्लाम से है। अरमान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा।
- बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद वहाँ निर्वाचित सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल मरहूम खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आगे चल रही है, जिसे उदारवादी छवि के कारण सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।
- लेकिन, जमात का बदलता रुख संकेत दे रहा है कि अपने भारत विरोधी और पाक समर्थक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी जमात भारत के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है।

पहली है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), और दूसरी है, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी है और समाज के सभी

वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ढाका-14 सीट से जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार अरमान एक हाईप्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं। वे बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के पीड़ित रह चुके हैं। वे बीएनपी की उम्मीदवार संजीदा इस्लाम उर्फ तुली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 'मदर्स कॉल' नाम के संगठन की समन्वयक हैं। यह संगठन जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों द्वारा बनाया गया है। अरमान ने कहा, “हम फिर से तानाशाही नहीं चाहते। मैं जबरन गायब किए जाने का शिकार रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनमत संग्रह में 'हाँ' की जीत होगी।” अरमान जमात के बड़े नेताओं में से एक हैं और भारत के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पैनग्विन रैंडम हाउस को नोटिस

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने पैनग्विन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना

- दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के मामले में इस पब्लिशिंग हाउस से जवाब तलाब किया है।

प्रमुख की पुस्तक को लेकर दर्ज मामले में और सीक्रेट एक्ट व कॉपी राइट की धाराएं भी जोड़ी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दौसा में बारात से लौट रहे छह युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत

सभी युवक एक ही गांव के थे तथा शादी-समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे



दुर्घटना से 30 मीनट पूर्व युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटो।

दौसा, (निसं)। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा उपखण्ड में स्थित ग्राम कैलाई के पास देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौके पर तथा दो की उपचार के दौरान मौत हो गई। सभी युवक एक ही गांव के हैं तथा शादी-समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस भीषण हादसे के बाद ग्राम कालाखो में हाहाकार मच गया तथा खुशियां मातम में बदल गईं। हादसा मंगलवार देर रात करीब बारह बजे हुआ, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रैलर से जा टकराई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक

- हादसा जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा उपखण्ड में स्थित ग्राम कैलाई के पास मंगलवार देर रात करीब बारह बजे हुआ, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रैलर से जा टकराई**
- प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए**

नियंत्रण बिगड़ने से वाहन सीधे डिवाइडर लांचते हुए विपरीत दिशा में पहुंच गया। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैलर से उसकी आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़

गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। इधर हादसे की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए



हादसे के बाद घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया, जहाँ उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे दिए। वहीं दूसरी ओर हादसे के बाद कुछ समय तक हाइवे पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन चालक का नियंत्रण खोना हादसे का कारण माना जा रहा है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रैलर चालक से भी पूछताछ की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। शादी से लौट रहे थे : हादसे में समय सिंह पुत्र रामसिंह योगी, लोकेश पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश पुत्र बनवारी योगी, मनीष पुत्र हरिमोहन योगी, अंकित पुत्र लालराम बैरवा तथा नवीन योगी की मौत हो गई ये सभी कालाखो के रहने वाले थे, रात्रि को एक शादी समारोह में शामिल होकर पुनः घर लौट रहे थे। लौटने से पूर्व सभी युवकों ने एक साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, इधर इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

जोधपुर में चार हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर ग्रामीण टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जोधपुर जिले के पटवारा हल्का खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा के पटवारी रोहित कुमार को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है।

शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण इकाई को बताया था कि आरोपी पटवारी रोहित कुमार उसकी दादी के नाम से जमीन के खाते में करेक्शन करने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जांच के दौरान यह बेरिफाई हुआ कि आरोपी ने पहले पांच हजार रुपए की डिमांड की, लेकिन शिकायतकर्ता की गुहार पर 4 हजार रुपए पर सहमत हो गया। एसीबी

- परिवादी की दादी के नाम से जमीन के खाते में करेक्शन करने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी**

के डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसीबी एएसपी जोधपुर ग्रामीण पारस सोनी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार को रिश्वत लेते मौके पर ही दबोच लिया। एसीबी महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ व कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

भरतपुर में लैब टेक्नीशियन से 25 हजार की रिश्वत ली

भरतपुर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भरतपुर के राजकीय जनाना चिकित्सालय स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट (बीएसयू) में कार्यरत लैब टेक्नीशियन (प्लेसमेंट कार्मिक) राम कुंवार को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि करौली चौकी को शिकायत मिली थी कि आरोपी परिवादी को जनाना चिकित्सालय भरतपुर में संविदा पर ट्रांली प्लर वाई

बॉय के पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर 30 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टैप कार्रवाई की गई। आरोपी ने परिवादी को जनाना चिकित्सालय में बुलाकर 25 हजार रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर, स्थाही, पेपरशीट जब्त

राजसमंद, (निसं)। केलवा थाना क्षेत्र में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नकली नोट और उपकरण जब्त किए हैं।

केलवा थाना अधिकारी सुबोध जांगिड़ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केलवा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जैतपुरा गांव में एक मकान में नकली नोट छापे जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दो युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आमेट

थाना क्षेत्र के आगल गांव निवासी नारायण लाल पुत्र मोहन लाल गुर्जर और कमलेश गुर्जर पुत्र मोहन लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के 15 नोट, 200 रुपये के 362 नोट और 50 रुपये के 4 नोट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 80 हजार 100 रुपये है। इन सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित मिला। मौके से जाली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर, स्थाही के कंटेनर, पेपरशीट, कट्टर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच का का जारी है।

पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कैथून पुलिस टीम ने इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के लिये कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा अपरेशन क्रिमिनल डिस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस ने बताया कि उसी अभियान के तहत कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने मय जाप्ता इलाके में कार्रवाई करते हुए एक जने से अवैध हथियार देशी पिस्टल बरामद की। पुलिस टीम ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए कैथून निवासी मोहम्मद शहिद उर्फ कालिया (34) को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी ने पूछताछ में सफल मेवाती से अवैध हथियार लाना बताया है, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

स्मैक तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास

जोधपुर, (कासं)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 16 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोक्ता एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 24 जून 2011 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने पीपाड़ से देवाताड़ा जाने वाली रोज से एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बंशीलाल पुत्र पोकरराम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डोंगियावास जोधपुर से 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया। गोविन्द जोशी विशिष्ट

लोक अभियोक्ता एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने एवं उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नस्ली बर्तने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 15 गवाह, 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 1 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त बंशीलाल पुत्र पोकर राम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डोंगियावास जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

कुएं में डूबने से युवक की मौत

उदयपुर,(कासं)। जिले के घासा थाना क्षेत्र में स्थित कुएं में डूबने से युवक की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को घासा थाना क्षेत्र में स्थित कुएं में युवक का शव होने की सूचना मिलने पर घासा थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह, एएसआई प्रेमशंकर ने मौके पर पहुंच कर मृतक को कुएं से बाहर निकाल उसकी शिनाख्त झालों का ढाणा नूरुद्दा निवासी बक्शराम उर्फ बक्शोराम रेबारी (50) पुत्र अर्जुनजी रेबारी के रूप में शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। एएसआई प्रेमशंकर ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाशव परिजनों को सौंप दिया। बक्शोराम मानसिक रोगी होकर महिला के कपड़े पहनकर इधर-उधर घूमता रहता था। शव करीब चार दिन पुराना बताया जाता है। कुएं में बंदवू आने पर लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे बाहर निकाल खेमली चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया था।

युवक ने घर में आत्महत्या की

जोधपुर, (कासं)। शहर के सूरसागर स्थित नारवा पुल के पास रहने वाले एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। इस बारे में मृतक के भाई की तफ़्फ़ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई।

सूरसागर पुलिस ने बताया कि मूलतः उन्डामर हाल नारवा पुल के पास संत लक्ष्मीदास नगर सूरसागर निवासी प्रेम पुत्र देवाराम सुथार ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रात्रि के समय उसके भाई राहुलराम ने घर में फंदा लगा लिया। पता लगने पर उसे फंदे से उतार कर अस्पताल लाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे चैक कर मृत बता दिया। पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजन को सौंपा।

पुलिस ने नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया

सीकर, (निसं)। बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र सदर सीकर में रात प्राप्त जागमालपुर में बाल अधिकांशता विभाग सीकर व गायत्री सेवा संस्थान एवं चाह्रुड हेल्थलाइन टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया।

गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बारात के स्वागत की तैयारियों के बीच पुलिस टीम अचानक मौके पर पहुंच गई। परिवार बारात का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि विवाह की रस्में शुरू होतीं, प्रशासन ने हस्तक्षेप कर नाबालिग की शादी रुकवा दी। जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि विवाह में शामिल दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम है। पुलिस के आधार पर पुलिस एवं टीम ने मौके पर पहुंचकर

- परिवार बारात का इंतजार कर रहा था और मौके पर पुलिस पहुंच गई**

दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आया कि नाबालिक बच्ची की उम्र 15 वर्ष है उम्र कम पाए जाने पर विवाह को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। अधिकारियों ने परिजनों को समझाइस की। पुलिस ने परिवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और नाबालिग को शिक्षा जारी रखने की सलाह दी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब दो साल से अधिक पुराने मामले में पॉक्सो क्रम-4 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोक्ता वंदना नागर ने बताया कि 27 दिसम्बर 2023 को पीड़िता के पिता ने कोटा ग्रामीण के एक थाने में शिकायत दी। शिकायत में कहा कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 दिसम्बर 2023 की रात्रि को बिना बताये कहीं चली गई। जब उसने देखा तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, कमरे में बेटी नहीं थी। शिकायत पर जांच कर भगाले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।

हमले में घायल पिता की मौत, बेटे ने की थी मारपीट

कोटा, (निसं)। जिला बूंदी के केशवरायपाटन थाना इलाके में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने पिता के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में घायल वृद्ध की एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

केशवरायपाटन थाने के एएसआई हरिशंकर शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के सोडेला गांव निवासी रामरतन के तीन बेटे हैं, जिसमें बड़ा और छोटा बेटा गांव से बाहर रहते हैं और एक बेटा लेखराज रामरतन के साथ रहता है। एएसआई ने बताया कि मंगलवार रात्रि को रामरतन और लेखराज के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और उसी झगड़े के चलते लेखराज ने लकड़ी से पिता के साथ मारपीट कर दी। हमले में घायल रामरतन को उपचार के लिये केशवरायपाटन के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां

हालत में सुधार नहीं होती देख उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करारक शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई ने बताया कि आरोपी लेखराज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

गांजे सहित एक गिरफ्तार : उदयपुर के बैकरिया थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध गांजे से भरी कार जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर अवैध गांजा जब्त किया। बैकरिया थानाधिकारी उत्तमसिंह मय टीम खजूरा घाटी कालीबोर कोटड़ा रोड़ पर कार को रोक चालक प्रकाश पुत्र नीलकंठ पुरोहित निवासी आनूपुर नउवा चन्देसरा डबोक को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 3 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया।

पुलिस वैन से टकराई कार, महिला थाना प्रभारी की मौत

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर मार दी। हादसे में महिला पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित दो लोग गंभीर घायल हुए हैं। हादसा श्रीगंगानगर शहर में पायल थियेटर रोड स्थित चौघाहे पर बुधवार सुबह चार बजे हुआ।

श्रीगंगानगर शहर में पायल थियेटर रोड स्थित चौघाहे पर बुधवार सुबह करीब चार बजे पुलिस की गाड़ी से कार की टक्कर हो गई।

जानकारी के अनुसार एसएचओ ज्योति नायक किसान चौक से पेट्रोलिंग करते हुए रमेश चौक के पॉइंट की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वैन पलट गई। झाड़वर के साइड वाली सीट पर बैठी एसएचओ ज्योति का सिर बुरी तरह से दब गया। इसी कारण उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं, टक्कर मारने वाली कार कुछ मीटर आगे टकराकर रुक गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वैन का अगला

- एक पुलिसकर्मी सहित दो गंभीर घायल, पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस टीम**
- हादसे में हरियाणा नंबर की कार के चालक को भी चोटें आई हैं। झाड़वर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है**

हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शहर कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने बताया हादसे में हरियाणा नंबर की कार के चालक को भी चोटें आई हैं। झाड़वर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक्सिडेंट में एक अन्य पुलिसकर्मी और कार चालक भी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही एसपी अमृता दुहन सहित पुलिस के अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे।

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR.			
No. NIT/2025-26/34700-14	निविदा सूचना/2025-26	Date: 11.02.2026	
निविदाहस्तारकी के लिए नोट: राज्य सरकार के अधिकाधिक विभागों एवं उनके अधिकृत संयंत्रों में पंजीकृत एवं अनुप्रीत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।			
कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित लागत (₹.)	निविदा सूचना संख्या	
SITC of HVAC work at Admin. Block Marwar Medical University of Borawar, Jodhpur.UBN: RRC2526WSOB01197	366.00 Lakh	ई-690/25-26	
Additional work Required at Medical College, Karnali. UBN: RRC2526WSOB02101	365.33 Lakh	अप्रकारित ई-691/25-26	
Construction of Outer Facade work at Sambhargya Kar Bihawan at Jaipur. UBN: RRC2526WSOB010203	1245.14 Lakh	ई-694/25-26	
निविदा से सम्बंधित प्रपत्र में निविदा सूचना, प्रयोगांश, हाइड्रोलेड फरमे व कोलोन की प्रतियां सहित समूचे विवरण से निर्माण के लिए आवश्यक एवं अनुप्रीत संवेदकों को अपने निविदात दस्तावेज के माध्यम से केसाईद। http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदात करवाना आवश्यक है।			
			महाराष्ट्र

निविदा से सम्बंधित पत्र सूचना, फील्ड ऑफ, डाक्यूमेंट करने व प्रवेश की प्रक्रिया और समुचित विवरण एवं संपर्क जानकारी: <http://sppp.raajasthan.gov.in> & <http://eproc.raajasthan.nic.in> एवं <http://pwwd.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों की अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नोखा

क्रमांक-3374-81

दिनांक 03.02.2026

Notice Inviting Bid- 12/2025-2026

Bids for Repair work and Strengthening and Renewal Work are invited from interested bidders upto 06.02.2026 [09.30AM] to 16.02.2026 [06 PM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <https://www.pwd.raajasthan.gov.in> & eproc.raajasthan.gov.in & <http://sppp.raajasthan.gov.in> of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 223.99 Lakh.

NIB CODE NO. PWD2526A5491, UBN-PWD2526WSOB22377, UBN-PWD2526WSOB22378, UBN-PWD2526WSOB22379, UBN-PWD2526WSOB22380

Executive Engineer
PWD Dn. Nokha

DIPR/C/2664/2026

राजस्थान सरकार	
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर	
स्वास्थ्य भवन, रत्यागी बाटिका, जेल वैन, बीकानेर	
फ़ोन-0151-2201142	email:eambhikaneer@gmail.com
क्रमांक-EE/M&H/BKN/2025-26/3309	दिनांक-29.01.2026
ई-टेंडरिंग निविदा सूचना संख्या-60/2025-26	
निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर में कुल रु. 228.49 लाख के 02 कार्य जो जिला अस्पताल पर विद्युत कार्य हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपयुक्त विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संयंत्रों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाटा एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एयरफोर्स इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त विद्युत श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बंधित विवरण DIPR की वेबसाइट www.dipronline.org http://eproc.raajasthan.gov.in व विभागों वेब साइट http://rajsawasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।	
UBN NO. 1. NRH2526WSOB02297	(शिम्पू राम जाटव)
2. NRH2526WSOB02298	अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/2352/2026	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

राजस्थान सरकार	
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर	
स्वास्थ्य भवन, रत्यागी बाटिका, जेल वैन, बीकानेर	
फ़ोन-0151-2201142	email: eamhbikaneer@mail.com
क्रमांक-EE/M&H/BKN/2025-26/3310	दिनांक-29.01.2026
ई-टेंडरिंग निविदा सूचना संख्या-61/2025-26	
निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर में कुल रु. 144.65 लाख के 02 कार्य जो जिला अस्पताल पर विद्युत कार्य हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपयुक्त विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संयंत्रों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाटा एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एयरफोर्स इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त विद्युत श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बंधित विवरण DIPR की वेबसाइट www.dipronline.org http://eproc.raajasthan.gov.in व विभागों वेब साइट http://rajsawasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।	
UBN NO. 1. NRH2526WSOB02299	
2. NRH2526WSOB02301	
(शिम्पू राम जाटव)	
अधिशाषी अभियन्ता	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर	
DIPR/C/2351/2026	

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा.अभि.विभाग, वृत्त चित्तौड़गढ़			
शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़-312001			
फ़ोन नं. 01472-240916	E-mail: secircle.chi.phed@rajasthan.gov.in		

भजनलाल सरकार ने विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 1० संकल्पों में पढ़ा सरकार का विजन



-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में 6.10 लाख करोड़ रुपए का तीसरा आम बजट 1० संकल्पों में पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाने, किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने, मेधावी छात्रों को 20 हजार रू. का ई-वाऊचर, परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी, स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटाटा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने तथा असहाय, विर्मदित, लावारिस मरीजों के फ्री इलाज की घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रू. किया। होमगार्ड्स के 5 हजार पद भी बढ़ाए गए है।

राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट आकार प्रस्तावित किया है। जो कि पिछले बजट से 52 हजार 360 करोड़ रू. ज्यादा है। बजट प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 5 लाख 25 हजार 740 करोड़ 34 लाख रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, राजस्व व्यय 3 लाख 50 हजार 50 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपये आंका गया है। सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए राजकोषीय घाटा 79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपये रहने का अनुमान जताया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.69 प्रतिशत होगा। आर्थिक प्रगति के संकेत देते हुए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि, सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसकी पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। कर्मचारी अगर

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2०26-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सत्ता पक्ष ने ठहाके लगाए।

सरकारी नौकरी में रहते हुए स्थायी दिव्यांग हो जाता है और वह नौकरी करने में असमर्थ है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में राज्य सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। इसके साथ ही 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 1० लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों

■ 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी गठन, किसानों को 25 हजार करोड़ रू. का ब्याज मुक्त ऋण तथा लावारिस-विर्मदितों के मुफ्त इलाज की घोषणा

■ मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रू. का ई-वाऊचर तथा स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारे की घोषणा

■ महिला वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की

से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है।

देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है।

इसी तरह किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा से मार्च-अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास है। मेधावी विद्यार्थियों को 20 हजार रुपए का ई-वाऊचर देने से भी इन तमाम परिवारों के बीच सरकार की पॉजिटिव ब्रांडिंग पहुंचाने की कोशिश है। वहीं स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटाटा लोगों के लिए कौतूहल व चर्चा का विषय छोड़ दिया है। इसी प्रकार बजट में लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने से भी महिला वर्ग को साधने का प्रयास है।

राजस्थान बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा स्टांप ड्यूटी पर सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा; डी.एल.सी. दरें भी बढ़ली

जयपुर (विसं)। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। इस निर्णय का असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर देखने को मिलेगा। यही नहीं सरकार ने कुछ अलग-अलग कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया है। इन दोनों ही निर्णय से अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी महंगी होगी।

बजट में सरकार ने बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को भी आधा कर दिया है। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस 1 फीसदी लगती थी, लेकिन इसे कम करके आधी यानी 0.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी। इसी तरह इन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी 0.25 फीसदी से आधा यानी (०.125 फीसदी) कर दिया है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

सरकार ने अब फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित दरों (डी.एल.सी. रेट) में भी बढोतरी की है। सरकार पहले फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहां की एग्रीकल्चर जमीन

■ हालांकि दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी

■ सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा किया

■ फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हुआ

की दर 1.5 गुना मानते हुए रजिस्ट्री करती थी। लेकिन फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य एग्रीकल्चर जमीन का 3 गुना मानते हुए रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह कोई रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य वहां की कृषि भूमि का 2 गुना रेट मानकर करते थे, लेकिन अब ये दर वहां की कॉमर्शियल रेट का 7.5 फीसदी रेट मानकर रजिस्ट्री की जाएगी।बजट में सरकार ने दूसरे राज्य से गाड़ी (प्राइवेट व्हीकल) स्थायी रूप से लाने पर उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स पर छूट दी है। वर्तमान में इस तरह की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स अलग-अलग वाहनों (क्षमता के अनुसार) पर अलग-अलग दर से लगता है, जिस पर सरकार अभी 2.5 फीसदी तक छूट देती है। सरकार अब ऐसी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स पर भी जाने वाली छूट को 2.5 से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की घोषणा की है।

सीकर और झुंझुनूं में एयरपोर्ट का सर्वे, अरावली के किनारे बनेगी पक्की दीवार

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा हिस्सा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में आता है। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से अरावली पर्वतमाला की करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि को जगह पर पक्की दीवार बनाई जाएगी। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों की सिग्नल फ्री

करोड़ की लागत से इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।

सीकर और झुंझुनूं में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा की गई है। 8 जिलों में 3000 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू होने की घोषणा की है। इस परियोजना पर 32000 करोड़ पए खर्च होगा।

बजट में प्रदेश के लिए प्रमुख घोषणाएं...

■ स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर और एलिवटेड रोड के निर्माण व मरम्मत पर 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे

■ नॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों पर 1400 करोड़ तथा मिसिंग लिंक सड़कों पर 600 करोड़ रू. खर्च होंगे

■ आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे

■ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्गों के विकास पर 400 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे

■ आगामी वर्ष भी मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया

■ राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों एवं शहरों में 2000 कैमरे स्थापित करने पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे

■ मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे

■ अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे

■ एक हजार 92 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति

■ आगामी वर्ष 600 टयूबवैल व 1200 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित

■ सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में ‘‘सेंटर ऑफ एक्सिलेंस’’ की स्थापना

■ प्रदेश में 220 केवी के छह, 132 केवी के तेरह तथा 33 केवी के 110 जीएसएस निर्माण

■ राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईट्स लगेंगी

■ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं को 10 लाख रू. तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान

■ रानी लक्ष्मी बाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना, लगभग 25 हजार छात्राये लाभान्वित

■ 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाऊचर

■ कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म

■ प्रदेश के सभी विद्यालयों में टायलेट सुविधा तथा 1000 स्कूलों में एआई लैंब की स्थापना

■ खेलों राजस्थान ‘‘यूथ गेम्स’’ का ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर आयोजन

■ प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मेंटल हैल्थ केयर सेल की स्थापना

■ जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का आईपीडी टावर

■ चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रिब्यूशन काउन्टर की स्थापना

■ मृतक के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क मोक्ष वाहिनी योजना

■ 7500 आंगनबाड़ियों का नन्द घर के रूप में विकास

■ खुड़ी-जेसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टयूरिज्म जोन तथा कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र

■ 100 करोड़ रुपये भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण।

■ झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों का संधारण

■ जैसलमेर , जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट तथा झुंझुनूं में वार म्यूजियम।

■ सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र की स्थापना

■ आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को वाट्सऐप प्लेटफोर्म पर भी शुरू

■ 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को ‘मिनी ई मित्र’ के रूप में अधिकृत

■ प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य 11 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से होंगे

■ आगामी वर्ष 50 हजार सोलर पंप संयंत्रों पर एक हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से होंगे

■ विभिन्न कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान, लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे

■ प्रदेश में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50-50 गोदामों का निर्माण

■ प्रदेश के चयनित जिलों में 2 हजार कृषकों , व्यापारियों व निर्यातकों को प्रशिक्षण

■ नवगठित जिलों में जिला सहारकी उपभोक्ता भंडार तथा सभी जिलों में नवीन उपहार विक्रय केंद्र

■ 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र तथा 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का क्रमोन्नयन

■ अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

■ आगामी वर्ष 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपये की लागत से वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्य

■ वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर-वन भूमि से एक हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक



सचिन पायलट

जयपुर (कासं)। कांोस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताया। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है। पायलट ने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद

■ सचिन पायलट ने कहा कि ‘‘पहले केन्द्रीय बजट में राजस्थान की अनदेखी हुई, अब राज्य सरकार ने भी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है।’’

■ पायलट ने कहा कि ‘‘हाईकोर्ट में सरकार ने हफलनामे के माध्यम से स्वीकार किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में मात्र 500 करोड़ रू. का प्रावधान दिखाता है कि सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है।’’

इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते राजस्व घाटा बढ़ा है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने शब्दों के मायाजाल से अपनी 2 वर्षों की नाकामी को छुपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ग्तु नेषों के बजट की भांति यह बजट भी हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद

कागजों तक सीमित रह गई है। सरकार अपने पिछले बजट्स की उपलब्धियों पर पूरी तरह मौन साधे हुए है। प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 4 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं होना और निजी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों का सांजजनिक न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। पायलट ने कहा कि नहरी क्षेत्रों में फार्म पौड की सब्सिडी दो साल से बंद पड़ी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी न करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग पर अमेरिकी टैट्रिफ के संभावित संकेत और सोलर पार्कों के नाम पर राज्यवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

पांच साल में 1०0 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा की थी, परंतु 2 साल में मात्र एक बना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई नई घोषणा नहीं किए जाने की चर्चाएं विधानसभा के गलियारों में रही। भाजपा ने राजस्थान में चुनाव लड़ने पूर्व अपने मैनिफेस्टो में घोषण की थी कि, हमारी सरकार बने के बाद 5 साल में 1०0 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। परंतु राज्य सरकार के बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हुआ है। जबकि गत 2 बजट में सरकार ने 19 केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की थी।

ज्ञात रहे कि इन ‘‘इंड्रिस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटरस’’ (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों) के महिलाओं समेत ऐसे युवाओं को सरकारी इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रशिक्षण देना था।

जयपुर । फैंडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरूण अग्रवाल ने राजस्थान सरकार के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे।

■ राजस्थान में युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई बजट में

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी छात्रों के साथ हुई चर्चा में कहा था कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं होते तो वह कौशल मंत्रालय का पदभार संभालते। प्रधानमंत्री का यह कथन दर्शाता है कि वे युवाओं और महिलाओं के रोजगार व कौशल विकास को लेकर गंभीर हैं, और शायद इसी वजह से राजस्थान में भाजपा ने भी 1०0 इण्डुस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (आई.टी.आई.) के निर्माण की घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद बीते 2 वर्ष में 19 आईटीआई स्थापना की घोषणा भी गत बजटों में हुई। परंतु बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक सिर्फ 1

आई.टी.आई. का निर्माण कार्य ही पूरा हो सका है। शेष 18 में से कुछ जगहों पर तो अभी भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। बजट आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने 10 आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिन 1० आई.टी.आई. का निर्माण किया जाना था उनमें एक-एक केन्द्र का निर्माण डौगाना-नागौर, बारां, दौसा, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, सल्म्बर में निर्माण होना था और दो केन्द्रों का निर्माण जयपुर में किया जाना था। परन्तु अभी तक नागौर, जयपुर और बांसवाड़ा में केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि आवंटन भी नहीं हुआ है। वहीं बजट घोषणा 25-26 में 9 अन्य आई.टी.आई. निर्माण करने की घोषणा की थी, जिनमें से केवल एक का ही निर्माण हुआ है जो विद्याधर नगर जयपुर में स्थित है।

विकसित राजस्थान का विजन : चतुर्वेदी ‘व्यापारियों व उद्योगों के लिए नई दिशा’

जयपुर । राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान बजट 2026-27 को समावेशी और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में गति देगा। चतुर्वेदी ने बताया कि बजट

गरीब, युवा, किसान, नारी, मजदूर और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आधारभूत ढांचा, उद्योग विस्तार, कृषि व पशुपालन सशक्तीकरण और निवेश प्रोत्साहन से रोजगार सृजन को बल मिलेगा। बजट के तहत वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए नई भर्तियां, कौशल

विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रावधान भी शामिल हैं। ग्रीन बजट के माध्यम से सौर, पवन और जल ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करते हुए

जयपुर । फैंडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) के कार्यकारी अध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अरूण अग्रवाल ने राजस्थान सरकार के बजट को व्यापारियों व उद्योगों को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री

एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, व्यापार प्रोत्साहन नीति, और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इनसे व्यापार करना आसान होगा और व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे।

हो पाई हैं। 30 प्रतिशत घोषणाएं अब तक शुरू नहीं हुईं, जबकि 4० प्रतिशत पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, जबकि वर्तमान समस्याओं की सुध लेने को तैयार नहीं है। रिफाइनरी शुरू करने की पूर्व घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा।



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

वर्ष 23-24 के मुकाबले इस वर्ष बजट का आकार 40 प्रतिशत बढ़ा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24-25 की 93 प्रतिशत तथा 25-26 की 86 प्रतिशत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हो गई

जयपुर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने, और सबका साथ, सबका

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष के बजट में वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए दोगुनी, चिकित्सा-स्वास्थ्य के लिए 53 प्रतिशत अधिक तथा ग्रीन बजट पर 20.81 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट में आधारभूत संरचना



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचन्द बैरवा मौजूद थे।

के सुदृढ़ीकरण सहित, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246

घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। ग्रीन बजट में 33 हजार 476

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है। शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टैस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

‘डॉक्टरों को उपभोक्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अनुचित व्यापार प्रथाओं या खामियों के लिए समाधान प्राप्त करने का एक तंत्र प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 के अपने फैसले में यह माना था कि चिकित्सा सेवाएं भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा”

के दायरे में आती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 1995 को दिए गए अपने फैसले में यह कहा था: चिकित्सक द्वारा एक मरीज को दी गई सेवा (जब तक कि डॉक्टर किसी मरीज को मुफ्त सेवा न दे रहे हों या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत सेवा प्रदान न कर रहे हों), परामर्श, निदान और उपचार (चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा दोनों) के रूप में दी गई

सेवा, अधिनियम के धारा 2(1)(0) के तहत “सेवा” के दायरे में आएगी।
“यह तथ्य कि चिकित्सा पेशेवर भारतीय चिकित्सा परिषद और/या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत स्थापित राज्य चिकित्सा परिषदों के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होते हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं कर सकता।”

पैनग्विन रैंडम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जब पुस्तक की स्थिति और अनधिकृत संस्करणों के कथित अवैध प्रसार के विरोध में दावे किए जा रहे हैं, जिससे प्रकाशक, पूर्व सेना प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां एक व्यापक सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गई हैं। पुलिस के अनुसार विशेष प्रकोष्ठ ने नोटिस के माध्यम से प्रकाशक से औपचारिक रूप से संपर्क कर कई सवाल पूछे हैं और उनके विस्तृत जवाब मांगे हैं।

‘राष्ट्रगीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, राष्ट्रीय गीत पर आधारित कई झांकियां प्रदर्शित की गई थीं। नए नियमों के तहत, राष्ट्रीय गीत के छह अन्तर्ों का संस्करण, जो 3 मिनट 10 सेकंड तक चलता है, विशेष सरकारी आयोजनों में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके मुकाबले, “राष्ट्रगान” जन गण मन 52 सेकंड का होता है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मृदंगम की ध्वनि राष्ट्रीय गान से पहले बजाई जाएगी। जब वन्दे मातरम् और जन गण मन दोनों बजाए जाएंगे, तो राष्ट्रीय गीत पहले बजाया जाएगा। पिछले नवंबर में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने “मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए गीत के महत्वपूर्ण अन्तरे हटा दिये थे।” मोदी ने कहा था कि “गीत को टुकड़ों में बांट दिया गया, और इससे देश के विभाजन के बीज बोए गए।” संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा के दौरान, सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और कहा-सुनी हुई थी।

‘तीन साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

‘आपने भारत माता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कहा गया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा और तकनीकी उत्पाद खरीदीगा। उन्होंने कहा, “हम मूर्खों की तरह खड़े हैं। हमारा टैरिफ 18 प्रतिशत तक बढ़ गया है... और उनका 16 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है।”
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया और गांधी से, जो विपक्ष के नेता भी हैं, अमेरिका के साथ हुए सवझौते पर अपने दावों के समर्थन में तथ्य पेश करने को कहा।
रिजिजू ने कहा, “भारत की प्रगति से आपको खुशी नहीं होती। कांग्रेस ने 2014 तक देश को कमजोर किया और अब असंतुष्ट है..”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को “अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री” भी बताया।

वृंदावन के होटल में उद्घाटन के दिन ही आग लगी

मथुरा, 11 फरवरी। वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित नव निर्मित सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद भीषण आग लग गई। आग लगते ही होटल के अंदर घना धुआं भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में तीन लोग झुलस गए, जबकि करीब 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर बाद अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुएं का गुबार फैल गया। होटल में मौजूद मेहमान और कर्मचारी घबरा गए ?

कई लोग कमरों और गलियारों में फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया।

हादसे में होटल मालिक सुभाष अग्रवाल के समथी हरिमोहन के बेटे विनीत की तबियत अधिक बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, आग की चपेट में आकर तीन लोग झुलस गए। घायलों में

- आग के दौरान 40 लोग अंदर फंस गए थे, तीन लोग झुलस गए हैं
- जिलाधिकारी ने बताया कि होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तथा होटल मालिक के परिवार के तीन लोग झुलस गए।

दो बच्चे कार्तिक और समर तथा एक महिला जिया शामिल हैं। सभी को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि रुक्मिणी विहार स्थित सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के दिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उन्होंने कहा, इस घटना में होटल मालिक के परिवार के तीन सदस्य झुलस गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है।

बताया जा रहा है कि होटल में कुल 24 कमरे हैं और बुधवार को ही इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था।

एस्टीन से मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई- हरदीप पुरी

नई दिल्ली, 11 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (11 फरवरी) को बजट सत्र के दौरान एस्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि युवा नेता (राहुल गांधी) को पता होना चाहिए कि एस्टीन फाइल्स गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जेफरी एपस्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात

■ राहुल गांधी द्वारा जिक्र किये जाने के बाद मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया।

अंतरराष्ट्रीय पीस इन्स्टीट्यूट (आईपीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहते हुए हुई थी। उन्होंने कहा, साल 2009 में जब मैं अमेरिका में राजदूत था, तब ये मुलाकात हुई। सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सार्वजनिक रूप से करीब 3 मिलियन ईमेल हैं। इसके 8 साल बाद मैं मंत्री बना। इस दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एस्टीन से उनकी मुलाकात केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई थी।

बांग्लादेश में जमात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने कहा, “भारत और बांग्लादेश एक-दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें साथ मिलकर काम करना होगा।”
इस बयान को इस रूप में देखा जा रहा है कि जमात, अपने पुराने इतिहास और पहले पाकिस्तान समर्थक रुख के बावजूद, भारत के साथ काम करने की संभावना तलाशने के लिए तैयार हैं। हाल के महीनों में भारत से दूरी बनाकर रखना बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं रहा है और यह सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर जमीनी सीमा भारत से लगती है। हालांकि बांग्लादेश के जानकारों के अनुसार, बीएनपी अभी आगे मानी जा रही है, लेकिन जमात ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है, जहाँ पहले वह कमजोर थी। पार्टी पर लगा प्रतिबंध

हटने के बाद उसने यह बढ़त हासिल की है और अब वह बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। जमात के अमीर डॉ. शाफीकुर रहमान ने कहा, सिर्फ एक साल पहले मेरी पार्टी को कमजोर माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि हमें बहुत कम सीटें मिलेंगी। आज जमात बहुमत के करीब खड़ी है। यह जनता की इच्छा है। जब जनता एकजुट होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।”

रितु तावड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महापौर तावड़े और उपमहापौर घाड़ी शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और राज्य सरकार इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करेगी।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओन्ड गाड़ी 1 साल तक की वारंटी के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

MARUTI SUZUKI

TRUE VALUE

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruetruevalue.com

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला धीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है।

TRUE VALUE CERTIFIED

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्म एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्ड्रीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्ड्रीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908